Frequent flyer Programrat

*28. SHRI RAMACHANDRAN ML-LAI: Wilt the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) the number of passengers who have joined the frequent flyer programme;

(b) the time normally taken for credit-ing the mileage points;

(e) whether any complaint came to the notice about the long deity in crediting the mileage points; and

(d) What are the new proposals for making programme attractive?

THE MINISTER OP CIVIL AVIATION AND TOURMM (SHRI GHULAM NABI A2AD): (a) The membership of the Frequent Flier Prog ramma is 21,500 at present.

lb) and (c) In the initial stages, soon after launch of the scheme the time required for crediting the mileage points was about four weeks and some complaints of delay were received. The system has been progressively improved and the time required for crediting the mileage points has been reduced to about two weeks at present.

(d) The programme has been progressively modified and the procedure* streamlined during the last one year to make it more attractive for consumers. Accrual period for 30000 mileage points was extended from one year to three yean and the members can club mileage points with theif spouses to reach the threshold provided both are members.

Future plans include partnership alliances With hotel chains, credit card companies, car rentals etc. to enable meraebrs to earn mileage points when utilising these services.

टिहरी बांध के संबंण में श्रेत पत्र

*29. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1995 के "दि ट्रिब्यून" में "ह्वाइट पेपर ऑन टेहरी डैम साइट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं ;

(ख)यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रबुद्ध एवं विश्ष्टि नागरिकों ने सरकार से टिहरी परियोजना से जुड़े विवादों के संबंध में रेत पत्र जारी करने की अपील की हैं;

(ग)यदि हां, तारे क्या सरकार ने इस अपील पर विचार किया हैं;

(घ)यदि हां, तो रेत प9 कब तक प्रकसशित किए जाने की संभावना हैं, और

(ड.)यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं?

विद्युत मंत्री (**श्री एन0के0पी0 साहणे**) : (क) से (ड.) जी हां। समाचार-पत्र मे उल्लेख किया गया है कि अनेक संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के टिहरी बांध के सभी पहलुओं के संबंध में श्रेत पत्र जारी किए जाने की मांग की हैं। सरकार ने टिहरी बांध परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अलग से विविध प्रत्योवेदना प्राप्त किए हैं।

सकार ने टिहरी बांध के सभी पहलुओं की विस्तारपूर्वक जांच की है और ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श के बाद ही परियोजना को क्रियाम्बित किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था।

इसलिए सरकार इस संबंध में श्रेत पत्र जारी करने का प्रस्ताव नहीं रखती हैं। तथापि, सरकार किसी भी नए तथा यथेष्ट मुद्दों , जो उठाए जा सकते हैं, कि जांच करने के लिए तैयार हैं।

हिन्दी फिल्मों मे अश्लील और उत्तेजनक दृश्यों में वृद्धि

*30. **श्री अनन्तराय जायसवाल**:

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दी फिल्मों में अश्लील और उत्तेजक दृश्यों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही हैं;

(ख)यदि हां, तो सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन किए जाने के बावजूद ऐसे दृश्यों में तेजी बढ़ोत्तरी होने के क्या कारण हैं ;

(ग)क्या सरकार इस संबंध में कोई दण्डात्मक कानून बनाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तों कब तक और यदि नहीं,तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के0पी0सिंह देव) : (क) अश्लील और उत्तेजक दृश्यों में वृद्धि संबंधी शिकायतें / प्रेस रिपोटें सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त की जाती हैं। इन रिपोटों को प्रमाणित करने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया हैं। सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनत्पत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही प्रदर्शित किया जाता हैं।

(ख)प्रश्न नहीं उठता।

(ग)तथा (घ) सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अणिनियम में निर्धारित दण्डों में वृद्धि करना प्रार्थिस हैं।

Evasion of payment of Import duty on marble

*31. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newt-item captioned "Importers carve a custom-made fraud in imported marble" appearing the Indian Express dated 9th June, 1995;

(b) if so, the details thereof; and

(c)'the action taken to curb such frauds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir. The Government is aware of the news item appearing in the Indian Exoress dated 9th June, 1995.

(b) and (c) Import of marbel again*' Advance Licences under Duty Exemption?! Scheme were noticed in the ports *of* Bombay and Nhava Sheva, Goods wer£ mostly imported against transferred! Advance Licences. The imports were therefore replenishment of the impute already used in the exports. In all cases where there was no evidence of imported marble having been used in the export products, goods were either charged to duty or allowed provisional clearance against bond under the custom, law. In cases where undervaluation was suspected, duty was charged at enhanced value provisionally. Higher export price* were in respect of articles in the nature of artifacts which are costly products of marble and therefore the allegation over invoicing is not correct. Some of the cases where contraventions have been noticed were adjudicated in terms of the provisions of Customs Act and in other cases action according to law is being taken. The allegation of fraud and collusion with Customs authorities in ths news-item is, therefore, not correct. T>re total value of import of marbles in the two ports for the period 1992-1995 (uptf 31.3.95) is only Rs. 14 crore* approximately. Hence, the allegation of a Rs. 100 crore fraud is also not correct

विदेशी बैंकों से ऋण

*32. **श्री दिविजय सिंह**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)भारत पर विदेशी बैंकों जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इतयादि का कुल कितना ऋण हैं और कुल ऋण पर प्रति वर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा हैं;